



संदर्भ संख्या AIACE/CENTRAL/2025 / 067/S

दिनांक: 30.10.2025

प्रति

अवर सचिव,

CMPF अनुभाग, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

ईमेल: so-cmpf@gov.in

विषय: कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे पर अनुरक सुझाव

मान्यवर,

हमारे पूर्व पत्र संख्या **AIACE/CENTRAL/2025/067 दिनांक 15 अक्टूबर, 2025** के संदर्भ में, जो कि कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना एवं मसौदा विधेयक (संख्या F. No. 20011/2/2021-CMPF दिनांक 8 अक्टूबर 2025) से संबंधित है, कृपया संलग्न/संलग्नक के रूप में हमारा “**पूरक सुझाव**” स्वीकार करें —

“अनुसूची-II एवं संबंधित धाराओं में एक वैकल्पिक प्रावधान सम्मिलित किया जाए, जिसके अंतर्गत वे सदस्य जो चाहें, उन्हें CMPS-1998 योजना से बाहर निकलने और संचित पेंशन कोष को चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का विकल्प दिया जाए।”

पूर्व में हमारे प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य वर्तमान **CMPS-1998 ढांचे** के अंतर्गत पेंशन का तर्कसंगत पुनरीक्षण एवं वृद्धि सुनिश्चित करना था। किन्तु, लम्बे समय से किसी ठोस कार्रवाई के अभाव तथा न्यायोचित पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलता को ध्यान में रखते हुए, हम अब एक **वैकल्पिक प्रस्ताव** प्रस्तुत कर रहे हैं —

जिसके अंतर्गत **CMPS-1998 पेंशन योजना को समाप्त कर दिया जाए तथा जो सदस्य चाहें उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज सहित पेंशन कोष वापस किया जाए।**

1998 से लेकर अब तक 27 वर्षों में न तो किसी व्यापक पुनरीक्षण का कार्य हुआ और न ही किसी बीमांकिक (actuarial) संतुलन का पुनर्मूल्यांकन। वर्तमान में सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन अत्यंत नगण्य है — कई मामलों में ₹1000 प्रति माह से भी कम — जिससे यह योजना सामाजिक रूप से निरर्थक और आर्थिक रूप से शोषणकारी बन गई है। पिछले दो दशकों से दर्जनों वाद-विवाद और न्यायालयीन मुकदमे इस बात के साक्ष्य हैं कि इस योजना में न तो न्यासीय (fiduciary) उत्तरदायित्व निभाया गया और न ही पेंशनभोगियों का विश्वास बना रह सका।

ड्राफ्ट CMPF (संशोधन) विधेयक, 2025 इस दीर्घकालिक अन्याय को सुधारने का एक अवसर प्रदान करता है। यदि कोई सार्थक सुधार या पेंशन वृद्धि संभव नहीं है, तो न्यायसंगत एवं तर्कसंगत उपाय यही होगा कि —

“इच्छुक कर्मचारियों/पेंशनरों को उनके पेंशन कोष को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस किया जाए तथा CMPS-1998 योजना को समाप्त किया जाए।”

यह कदम **दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद (win-win)** स्थिति उत्पन्न करेगा —

पेंशनधारकों को एक उचित और आकर्षक राशि प्राप्त होगी, वहीं CMPF को पेंशन वितरण हेतु भविष्य की निधि व्यवस्था के बोझ से मुक्ति मिलेगी।

यह पहल CMPF की साख को पुनः स्थापित करने के साथ-साथ कोयला कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में **गरिमा, न्याय और पारदर्शिता** बहाल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगी, जैसा CMPF अधिनियम, 1948 के तहत कल्पित किया गया था।

सादर,

(पी. के. सिंह राठौर)

Principal General Secretary

संलग्न: उपर्युक्त अनुसार हमारे पूरक सुझाव (Annexure-I के रूप में)

प्रतिलिपि (CC):

- माननीय कोयला एवं खनन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
- सचिव (कोयला), भारत सरकार, नई दिल्ली
- श्रीमती रूपिंदर बराड़, अतिरिक्त सचिव (कोयला), भारत सरकार, नई दिल्ली



द्वितीय अनुसूची
(धारा 21 की उपधारा (2) देखें)

कोयला खदान कर्मचारी पेंशन योजना में प्रावधानित विषय

मसौदा विधेयक के मुख्य प्रावधान	हमारी टिप्पणियाँ/सुझाव
मसौदा विधेयक में अनुसूची-II कोयला खान पेंशन योजना (संशोधित) के लिए रूपरेखा को रेखांकित करती है, जो केंद्र सरकार को पेंशन लाभों को संशोधित या पुनर्गठित करने का अधिकार देती है।	(ए) अनुसूची-II (वैकल्पिक योजना प्रावधान) के अंतर्गत प्रस्तावित समावेशन: “7. पेंशन योजना से बाहर निकलने और कोष की वापसी का विकल्प: (1) इस अधिनियम अथवा पेंशन योजना में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, कोई भी कर्मचारी, पेंशनभोगी या उसका विधिक उत्तराधिकारी, <i>Coal Mines Pension Scheme, 1998</i> से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है। (2) इस विकल्प के पश्चात सदस्य को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान से संचित पेंशन कोष, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापसी का अधिकार होगा। (3) जो पेंशनभोगी पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा प्राप्त पेंशन की राशि को वापसी योग्य कोष से समायोजित किया जाएगा। (4) केंद्र सरकार, कोष के न्यास मंडल (Board of Trustees) से परामर्श कर, ऐसी वापसी की गणना, प्रमाणीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगी।” ** (बी) अनुभाग 3ई (या संबंधित पुनः क्रमांकित अनुभाग) में सुझाया गया क्रॉस-रेफरेंस: प्रस्तावित अतिरिक्त उपधारा (Sub-section 7) – “यह भी उपबंध किया जाए कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन योजना अपनी निर्धारित सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल हो जाए, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा योगदानकर्ताओं को उनके कोष की राशि उचित ब्याज सहित वापस लेने का विकल्प प्रदान कर सकेगी।” (सी) उद्देश्यों और कारणों के विवरण में सुझाया गया उल्लेख (कानूनी स्पष्टता के लिए): “यह विधेयक, <i>Coal Mines Pension Scheme, 1998</i> के अंतर्गत योगदानकर्ताओं को कोष वापसी का विकल्प प्रदान करने का भी प्रयास करता है, ताकि दीर्घकालिक पेंशन स्थिरता, बीमांकिक असंतुलन तथा वित्तीय अन्याय की स्थिति में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।”

Justification for our Proposal (हमारे प्रस्ताव का औचित्य):

- **उद्देश्य की विफलता:** CMPS-1998 योजना सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा देने में विफल रही है; इसका यथास्थिति में बने रहना अनुचित है।
- **स्वामित्व की पुनर्स्थापना:** प्रस्तावित उपधारा से योगदानकर्ताओं को उनके अधिकारपूर्ण कोष को ब्याज सहित पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- **राजकोषीय संतुलन (Fiscal Neutrality):** कोष वापसी से भविष्य की पेंशन देनदारियों और न्यायिक व्यय का बोझ घटेगा।
- **सामाजिक न्याय:** यह संशोधन उन वृद्ध श्रमिकों की गरिमा बहाल करेगा, जिन्हें दशकों से न्यायपूर्ण पेंशन से वंचित रखा गया है।





ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)

302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)

E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

Ref No. AIACE/CENTRAL/2025 / 067/S

Dated 30.10.2025

To

The Under Secretary,

CMPF Section, Ministry of Coal, Government of India,

Shastri Bhawan, New Delhi – 110001

Email: so-cmpf@gov.in

Sub: Supplementary Suggestion On The Draft Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2025

Dear Sir,

Further to our earlier submission vide our letter no. AIACE/CENTRAL/2025/067 dated 15th October, 2025 on the official notification and draft bill issued by the Ministry of Coal (F. No. 20011/2/2021-CMPF dated 8 October 2025), please find enclosed/attached herewith our supplementary suggestion on ***"Inclusion of an alternative provision under Schedule-II and related sections to allow refund of pension corpus with compound interest and discontinuation of CMPS-1998 to those members who opt for this."***

Earlier, our representation had focused on the urgent need to rationalise and enhance pension under the existing CMPS-1998 framework. However, considering the prolonged inaction and systemic failure to secure fair pensionary justice, we hereby submit an alternative proposal recommending withdrawal of the CMPS-1998 pension scheme and refund of the pension corpus with compound interest to those contributors who are willing to opt for this.

In the 27 years since its inception, no comprehensive revision or actuarial rebalancing has ever been implemented. The pension amount paid to retired coal employees is grossly inadequate—in many cases less than ₹1000 per month—rendering the scheme socially meaningless and financially exploitative. Numerous court cases and representations over two decades show a complete failure of fiduciary responsibility and erosion of pensioners' faith in the system.

The Draft CMPF (Amendment) Bill, 2025, offers an opportunity to correct a long-standing injustice. In the absence of meaningful reform or pension enhancement, the logical and equitable remedy is to allow for ***"Refund the pension corpus to willing worker/pensioner with 12% compound interest and discontinue the CMPS-1998 scheme."*** This will be a win-win situation for both, the pensioners/subscribers will have an opportunity to receive a handsome refund amount while CMPF will be relieved of arranging fund for pension disbursement.

This action has the potential to restore credibility of CMPF accompanied with restoration of dignity, fairness, and transparency to the coal workers' social security framework envisioned under the CMPF Act, 1948.

Yours sincerely,

(P. K. SINGH RATHOR)

Principal General Secretary

Encl: Our Supplementary Suggestions, as above, in Annexure-I

CC

1. Hon'ble Minister for Coal and Mines, Govt of India, New Delhi

2. The Secretary (Coal), Govt of India, New Delhi

3. Smt. Rupinder Brar, Addl Secy (Coal), Govt of India, New Delhi



THE SECOND SCHEDULE (See sub-section (2) of section 21)	
MATTERS TO BE PROVIDED FOR IN THE COAL MINES EMPLOYEES' PENSION SCHEME	
Salient Provisions in Draft Bill	Our Comments/Suggestions
Schedule-II in the draft bill outlines the framework for the Coal Mines Pension Scheme (Revised), empowering the Central Government to modify or restructure pension benefits.	(A) Proposed Inclusion under Schedule-II (Alternative Scheme Provision): Proposed to insert an Additional Clause (to be inserted as Clause 7 or at suitable location in Schedule-II): “7. Option for Withdrawal from Pension Scheme and Refund of Corpus: (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Pension Scheme, any employee, pensioner, or legal heir may exercise an option for withdrawal from the Coal Mines Pension Scheme, 1998. (2) Upon such option, the member shall be entitled to refund of the total pension corpus accumulated out of employee's and employer's contributions, along with interest compounded annually at the rate of twelve percent (12%) per annum from the date of contribution. (3) For pensioners already drawing pension, the amount of pension received till the date of such option shall be deducted from the payable corpus. (4) The Central Government may prescribe the procedure for determination, certification, and payment of such refunds in consultation with the Board of Trustees of the Fund.”**
	(B) Suggested Cross-reference in Section 3E (or corresponding re-numbered section): Proposed Addition (Sub-section 7 or as suitable): “Provided further that where the continuance of a Pension Scheme under this Act ceases to serve its intended social security objective, the Central Government may, by notification, permit refund of individual corpus with due interest to the contributors as an alternative to pension.”
	(C) Suggested Mention in Statement of Objects and Reasons (for legal clarity): “The Bill also seeks to empower contributors under the Coal Mines Pension Scheme, 1998 to exercise an option for withdrawal and refund of corpus with interest, in view of prolonged stagnation of pension benefits and actuarial imbalance, ensuring fairness and protection of workers' financial rights.”

Justification for our Proposal:

- Failure of Objective: The CMPS–1998 has failed to deliver meaningful post-retirement security; continuation without revision is unjustifiable.
- Restoration of Ownership: The proposed clause allows contributors to reclaim their rightful corpus with accrued interest.
- Fiscal Neutrality: Refund of corpus will reduce future pension liability and litigation costs for the government/CMPFO.
- Social Justice: This amendment restores dignity to aged mine workers who have been denied fair pensionary treatment for decades.

